

एसेट डिस्पोजल कमेटी (एडीसी), जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति दिलीप कृष्ण सेठ (सेवानिवृत्त) द्वारा की जा रही है और जिसमें ईडी के अधिकारियों की टीम शामिल है, ने रोज़ वैली पोंजी योजना के 3762 पीड़ितों/जमाकर्ताओं को 2.29 करोड़ रुपये और वितरित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। वर्तमान वितरण के साथ अब तक कुल 21,98,26,744 रुपये 32,319 पीड़ितों को वितरित किए जा चुके हैं। विभिन्न चरणों में की गई प्रगति का विवरण निम्नलिखित है:

चरण	जमाकर्ताओं / प्रमाण पत्र धारकों की संख्या	ितित्रीरेत	असफल लेन-देन वाले जमाकर्ताओं की संख्या	की गई (भ्रमफल	सफल लेन- देन की शुद्ध संख्या	शुद्ध वितरित राशि
I	7346	5,12,51,111	29	1,88,520	7317	51,06,25,591
II	6501	4,43,38,647	31	2,28,100	6471	44,11,05,47
III	8945	6,38,69,739	28	1,87,270	8917	63,68,24,69
IV	5895	3,79,87,993	21	1,25,820	5853	37,86,21,73
V	3762	2,31,08,964	21	1,45,700	3741	2,29,63,264
कुल	32,449	22,05,56,454	130	7,29,710	32,319	21,98,26,744

एडीसी की अध्यक्षता में हुई इस कमेटी में, ईडी, कोलकाता ने रोज़ वैली समूह की संपत्तियों की संपत्ति की जब्ती, कब्ज़ा और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम आदि राज्यों के हजारों पीड़ितों को संपत्तियों का पुनर्संवितरण सुगम और तेज़ हुआ। ईडी, एडीसी को पुष्टि की गई संपत्तियों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने में सिक्रय रूप से सहायता कर रहा है और संपत्तियों का शीघ्र मुद्रीकरण कर रोज़ वैली समूह के निवेशकों/पीड़ितों को वितरित करने में मदद कर रहा है।

आगे का पुनर्सवितरण प्रक्रिया आने वाले महीनों में जारी रहने की संभावना है क्योंकि और अधिक दावे एडीसी द्वारा जांचे और सत्यापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 25/02/2025 तक, एडीसी ने 32,319 दावों की प्रक्रिया की है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 22 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि ईडी ने व्यापक और श्रमसाध्य जांच के माध्यम से 494 करोड़ रुपये की मूवेबल संपत्तियाँ और 1,069 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्तियाँ जब्त की हैं, जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में फैली हुई हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल अकेले 1,184 करोड़ रुपये की संपत्तियों के साथ जब्त की गई हैं। यह एजेंसी के प्रयासों की निरंतरता को दर्शाता है जो रोज़ वैली समूह के धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए हैं। पुनर्सवितरण प्रक्रिया अब इन सभी क्षेत्रों में पूरी ताकत से चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय एडीसी की सहायता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है ताकि अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) को पीड़ितों को लौटाया जा सके।

